साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Global School Of Excellence, Obedullaganj

वर्ष : 9, अंक : 20 (प्रति बुधवार),इन्दौर, 3 जनवरी 2023 से 9 जनवरी 2024 पेज :8 कीमत : 3 रुपये

पर्यावरण मंत्रालय दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को रोकने और कम करने के लिए उठा रहा है कदम

नई दिल्ली। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा 2023 में दिल्ली-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) प्रोग्राम की समीक्षा की गई थी। इस बारे में छह अक्टूबर, 2023 को निर्देश संख्या 77 भी जारी की गई।

अपने इस निर्देश में आयोग ने कहा कि हवा को बेहतर बनाने के लिए तत्काल प्रभाव से दिल्ली-एनसीआर में जब भी जरूरी हो विभिन्न चरणों में इस योजना पर अमल करने की जरूरत है। यह जानकारी दो जनवरी, 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) द्वारा सौंपी गई कार्रवाई रिपोर्ट में कही गई हैं। यह रिपोर्ट दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के लिए उठाए कदमों के बारे में है। बता दें कि ग्रेडेड रिस्?पॉन्?स एक्?शन प्?लान यानी ग्रैप, आपातकालीन उपायों का एक सेट है, जो दिल्ली-एनसीआर में तय सीमा पर पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए लागू किए जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें अक्टूबर 2023 में कुछ बदलाव किए गए थे। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर सहित देशभर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। इनमें से एक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम नामक योजना है। साथ ही उद्योगों और पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय करना, वाहनों से होते उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाना और कचरे का बेहतर प्रबंधन जैसे कार्य इसमें शामिल हैं। यह रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी निर्देशों के बाद सौंपी गई है, ताकि कोर्ट को यह बताया जा सके कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के दौरान ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) नामक एक विशेष योजना लागू की जाती है। यह योजना वायु गुणवत्ता की स्थिति कितनी खराब है, इसके आधार पर विशिष्ट कदम उठाने के बारे में बताती है। वायु प्रदूषण को कम करने के इन उपायों को लागू करने के लिए विभिन्न एजेंसियां जिम्मेवार होती हैं। बता दें कि खासकर सबसे ठंडे महीनों के दौरान पूरे दिल्ली-एनसीआर में हवा आमतौर पर सबसे ज्यादा प्रदूषित रहती है। यह तय करने के लिए कि नए वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (सीएएक्यूएमएस) कहां लगाए जाएं और उन्हें कहां स्थानांतरित किया जाए, इसके लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोडल एजेंसियां होंगी। बता दें कि 30 जून, 2024 तक कुछ स्टेशनों को स्थानांतरित करने 31 दिसंबर, 2024 तक योजनानुसार सभी नए स्टेशन स्थापित करने की योजना है। यह स्टेशन भूमि उपयोग, आबादी के घनत्व, शहरीकरण आदि कारकों को ध्यान में रखते हुए स्थापित किए जाएंगें। यह जानकारी एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए बनाए आयोग ने अपनी एक जनवरी 2023 को जारी रिपोर्ट में दी है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), डीपीसीसी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) इस बारे में जानकारी अपडेट करेंगे कि प्रदूषण कहां से आता है और साथ ही वो पूरे एनसीआर क्षेत्र में इसके स्रोतों का पता लगाने के लिए अध्ययन करेंगे। उनकी योजना दिल्ली और आसपास के जिलों जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद के लिए 30 जून, 2024 तक और एनसीआर के अन्य जिलों के लिए 31 दिसंबर, 2024 तक यह काम पूरा करने की है। वहीं उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए, कुछ अन्य उपाय किए जाएंगें, इनमें औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले सामान्य बॉयलरों के लिए मानक और दिशानिर्देश बनाना, एनसीआर में गैस संबंधी बुनियादी ढांचे को तैयार करना और आपूर्ति शुरू करना शामिल है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना कि एनसीआर में हमेशा बिजली की आपूर्ति बनी रहे ताकि जनरेटर की जरूरत न पड़े।

हाल ही में मिचौंग चक्रवात के दौरान एन्नोर क्रीक और बकिंघम नहर में तेल का रिसाव हुआ था। इसके बाद वन विभाग के दल ने विशेष रूप से एन्नोर, अड्यार और कोसाथलाई क्षेत्रों में पक्षियों पर तेल रिसाव के प्रभावों की जांच की थी। इस बारे में तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी है कि टीम द्वारा किए सर्वेक्षण के दौरान कोई मृत पक्षी नहीं पाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 20 दिसंबर, 2023 तक कुल 105,280 लीटर तेल युक्त पानी और 393.7 टन तैलीय कीचड़ को वहां से निकाल दिया गया है। इस पानी और कीचड़ को आगे के उपचार और निपटान के लिए सीपीसीएल परिसर ले जाया गया है। बता दें कि एक निजी समाचार चैनल ने बकिंघम नहर में तेल फैलने से हो रहे प्रदूषण के बारे में जानकारी दी थी। चैनल के मुताबिक बकिंघम नहर में बहुत सारा तेल फैल चुका है और वो एन्नोर क्रीक तक पहुंच गया है। इसके अंश मछुआरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली नावों पर भी चिपके पाए गए हैं, जिससे उनकी गतिविधियों पर असर पड़ा है। वहीं 16 दिसम्बर 2023 को सोशल मीडिया से पुलिकट क्षेत्र के समुद्र तटों पर तेल युक्त कचरा फैलने की खबर के आधार पर अधिकारियों द्वारा उक्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया था। टीम ने कोराईकुप्पम और कूननकुप्पम मछुआरों की बस्तियों से सटे समुद्र तटों पर भी टार बॉल्स देखे थे। वहां से दल ने सफलतापूर्वक टार बॉल्स को हटा दिया है और करीब 12 किलोग्राम कचरा एकत्र किया है।

साभार

नया वर्ष भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के लिए एक गंभीर पुनरावलोकन लेकर आया

नया वर्ष भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के लिए एक गंभीर पुनरावलोकन लेकर आया- सन 1901 के बाद 2023 आधिकारिक रूप से सबसे गर्म वर्ष रहा। आईएमडी के मुताबिक जमीन का वार्षिक औसत सतह तापमान दीर्घकालिक औसत से 0.65 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा और 0.71 डिग्री का वार्षिक माध्य भी गर्म रहा। अनियंत्रित मौसम एक दूसरी कहानी है- आईएमडी ने कहा कि फरवरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर और दिसंबर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान मौसम के सामान्य तापमान से ऊपर रहा। बारिश के रुझान में भी अत्यधिक बदलाव देखा गया। उदाहरण के लिए उत्तर और उत्तर पूर्व के इलाके को छोड़ दिया जाए तो दिसंबर का महीना असाधारण रूप से अधिक बारिश वाला रहा और इस दौरान सामान्य से 60 फीसदी अधिक बारिश हुई। दक्षिण में मॉनसून के बाद के मौसम में 2011 के बाद सर्वाधिक बारिश हुई और 1901 के बाद यह बारिश का दसवां सबसे ऊंचा स्तर था। हिंद महासागर में छह ऊष्णकटिबंधीय तूफान देखे गए जो सामान्य से ऊपर थे। इनमें से तीन तो गहरे चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गए। मौसम के इस प्रकार के बदलाव के लिए अल नीनो को वजह बताया जा रहा है जिसने 2023 में वैश्विक तापमान को रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ा दिया। परंतु दो से सात वर्ष के लिए सामने आने वाली इस प्रक्रिया को लेकर नीतिगत निष्क्रियता नहीं होनी चाहिए। हाल के वर्षों के जलवायु संबंधी रुझान को देखें तो अल नीनो को केवल एक और योगदानकर्ता माना जा सकता है। भारत के मौसम के इतिहास में पांच सबसे गर्म वर्ष बीते 14 सालों में हुए हैं। तीव्रता के अनुसार ऐसे अन्य वर्ष थे- 2009, 2017 और 2010। औसत तापमान में निरंतर वृद्धि के दीर्घकालिक परिणाम काफी नुकसानप्रद हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा और वित्त से संबंधित अपनी 2022-23 की रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन को केंद्र में रखने का निर्णय लिया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि जलवायु परिवर्तन और अनियंत्रित मॉनसून वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा हैं। उसने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को सकल घरेलू उत्पाद के दो फीसदी के बराबर नुकसान हो सकता है तथा इसकी वजह से 2050 तक देश की आधी आबादी के जीवन स्तर पर असर पड़ सकता है। भारतीय कृषि और विनिर्माण उद्योग दो सबसे बड़े नियोक्ता और उद्योग हैं तथा लू के थपेड़ों के कारण उनकी उत्पादकता पर बुरा असर पड़ा है। यह बात भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धी बढ़त को नुकसान पहुंचाने वाली साबित हो सकती है। विश्व बैंक का अनुमान है कि 2030 तक बढ़ती गर्मी और लू के थपेड़ों के कारण दुनिया भर में उत्पादकता की कमी के कारण रोजगार को जो हानि होगी उसमें से 40 फीसदी भारत में होगी। इस कमजोर पूर्वानुमान में एक बात यह भी शामिल है कि जलवायु परिवर्तन के असर से सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब भारतीय होंगे। यह बात तो इस वर्ष टमाटर, प्याज, आलू, मिर्च और जीरा आदि की ऊंची कीमतों से ही सामने आ गई। सरकार ने हाल के समय में खानेपीने की चीजों के निर्यात को कम करने का निर्णय लिया है और उसकी वजह भी यही थी कि मौसम में बदलाव के चलते उत्पादकता में कमी आई। अकेले पिछले वर्ष का अनुभव ही यह बताता है कि भारत में जीडीपी में कार्बन उत्सर्जन में 2030 तक कमी लाने की रणनीतियों को तेज करने की आवश्यकता है। भारत को कार्बन उत्सर्जन तथा जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए भी पर्याप्त बजट की आवश्यकता होगी। नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में इजाफे के बावजूद निकट भविष्य में ताप बिजली संयंत्र ही मुख्य रूप से बिजली का उत्पादन करेंगे। समुचित विकल्पों के अभाव में भारत अपनी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के लिए कोयले पर निर्भर रहेगा लेकिन उसे नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश में भी इजाफा करना चाहिए ताकि बढ़ती गर्मी और जलवायु परिवर्तन के असर को कम किया जा सके।

पर्यावरण की शुद्धि के लिए घरों में हवन करने का संकल्प लिया

सफीदों। कलीराम डीएवी पब्लिक स्कूल में शनिवार को राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के सात दिवसीय कैंप का शुभारंभ किया गया। स्वयंसेवकों ने हिंदी में हवन करना सीखा और पर्यावरण की शुद्धि के लिए घरों में हवन करने का संकल्प लिया। प्राचार्या रश्मि विद्यार्थी ने स्वयंसेवकों को व्यक्तित्व निर्माण के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि एनएसएस का अर्थ ही सेवा भावना है। परिवार, समाज व देश के प्रति समर्पण, सहयोग करके या जिम्मेदारियों के प्रति दृढ़ संकल्प होकर ही युवा संस्कारित बन सकते हैं।

समाज के हर वर्ग को शिक्षित व जागरूक करना , सबका सहयोग करना, परिवार ,समाज व देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझना, पर्यावरण सुरक्षा करना, लोगों को साक्षर बनाना व सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूक करना स्वयंसेवकों का धर्म है। एनएसएस इंचार्ज रमनदीप कौर ने बताया कि हर्षिता, हर्षदीप, लवलेश, समृद्धि आदि स्वयंसेवकों ने कैंप में प्रथम दिन %% पर्यावरण बचाओ %% विषय पर पोस्टर बनाकर प्रदूषित पर्यावरण के बढ़ते खतरे के प्रति सचेत कर सुंदर व स्वच्छ प्राकृतिक सौंदर्य से रूबरू करवाया। स्वच्छ पर्यावरण का संदेश देने के लिए एनएसएस के सभी छात्र सुंदर फूलों के गमले लाए। प्राचार्या ने बताया कि कैंप के दूसरे दिन स्वयंसेवक सिंहपुरा गुरुद्वारा में श्रमदान करेंगे। पहले दिन ही बच्चों ने स्लोगन लिखकर जागरूकता रैली की तैयारी भी की। इस अवसर पर सूबे सिंह, सुनीता कंधवाल आदि मौजूद रहीं।

स्टोन क्रशरों को ग्रीन श्रेणी में रखने से पर्यावरण के लिए पैदा हो जाएंगी गंभीर समस्याएं

मुंबई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने जुलाई 2023 में उद्योगों को लाल, नारंगी, हरे और सफेद श्रेणियों में वर्गीकृत करने और उनके मानदंडों के लिए एक नया मसौदा पेश किया था। दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने इस ड्राफ्ट के साथ वर्गीकरण के लिए प्रस्तावित संशोधनों और उसकी पद्धति की भी समीक्षा की है।

सीएसई के मुताबिक, इस पद्धति में खामियां हैं क्योंकि इसमें आम लोगों और उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य पर पड़ते विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के प्रभावों को ध्यान में नहीं रखा गया है। इसके अलावा, खतरनाक वायु प्रदूषकों और कोयला या तरल ईंधन को जलाने से होने वाले उत्सर्जन की तुलना में देखें तो इसमें प्रक्रिया संचालन और सामग्री प्रबंधन से होने वाले क्षणिक उत्सर्जन को कम महत्व दिया गया है। इसके कारण, स्टोन क्रशर इकाइयां जोकि फ्यूजिटिव एमिशन के मामले में सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले क्षेत्रों में से एक हैं, उन्हें इस सीपीसीबी रिपोर्ट में नारंगी से हरी श्रेणी में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसी तरह स्टोन क्रशरों से होने वाले धूल उत्सर्जन को भी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि यह दूसरे खतरनाक वायु प्रदूषकों की तरह ही हानिकारक है। भारत में किए कई अध्ययन भी इस तथ्य को साबित करते हैं कि स्टोन क्रशर टोटल सस्पेंडेड पार्टिकल्स (टीएसपी) और सूक्ष्म कणों (पीएम 10) के साथ-साथ पीएम2.5 जैसे महीन कणों को भी पैदा करते हैं।

सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपने एक अध्ययन में चेन्नई के उपनगर पम्मल में मौजूद 50 स्टोन क्रशर इकाइयों की जांच की थी। इस शोध से पता चला कि ये इकाइयां बड़ी मात्रा में धूल पैदा करती हैं, जो आसपास के समुदायों को प्रभावित करती है। शोधकर्ताओं ने वहां टीएसपी, पीएम10 और पीएम2.5 के दैनिक स्तर को मापने के लिए जो 26 सैंपलिंग साइटें स्थापित की थी, उनमें टीएसपी का स्तर 342-2,470 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, पीएम10 का स्तर 90-1,200 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर जबकि पीएम2.5 का दैनिक स्तर 41-388 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक दर्ज किया गया। इतना ही नहीं इनमें से अधिकांश स्थानों पर आसपास के वातावरण में फैला प्रदूषण और व्यावसायिक जोखिम दोनों भारत के राष्ट्रीय मानकों से अधिक थे। राजपलायम तालुका में स्टोन क्रशर श्रमिकों के स्वास्थ्य पर पड़ते प्रभावों को लेकर किए एक अध्ययन से पता चला है कि भले ही स्टोन क्रशिंग इकाइयां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करती है, लेकिन साथ ही हमें इसके पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

कॉप 28 से आगे का रास्ता

दुबई दुबई में हुए जलवायु परिवर्तन पर 28वें कॉन्फ्रेंस (कॉप 28) का परिणाम क्या रहा, किन मुद्दों पर वार्ताएं हुई। इस पर डाउन टू अर्थ ने विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, जिसे पांच भागों में प्रस्तुत किया जा रहा है। अब तक आपने पढ़ा, भाग 1 = जानिए यहां कॉप 28 रहा कितना सफल, भाग 2 = यहां जानिए कॉप 28 के अहम फैसले और देशों की राय , भाग 3 = कॉप 28 में उत्सर्जन को खत्म करने के लिए क्या बनी रणनीति, यहां जानिए ।

विकसित और विकासशील की विभाजनरेखा पर अवस्थित एक देश द्वारा आयोजित कॉप 28 के सम्मेलन में जो परिणाम सामने आये, उन्हें ध्यान में रख कर विचार किया जाए तो बीते कॉप सम्मेलनों की तरह यह कॉप सम्मेलन भी न तो पूरी तरह सफल रहा और न ही बहुत सार्थक सिद्ध हो पाया। बांग्लादेश ने कहा पहली बार ऐसा हुआ कि हम सभी अपनी-अपनी सहज स्थितियों से से बाहर आकर जटिल स्थितियों को व्यापकता के साथ देख रहे थे। वहीं, वेनेजुएला ने कहा सम्मेलन की कमियों को स्वीकार किया गया। साथ ही जीवाश्म ईंधनों के मामले में विकसित देशों को आगे बढ़ कर नेतृत्व करने की आवश्यकता पर बल दिया गया हालांकि इसे मसौदे में नहीं दिखाया गया है। भारत का रुख यह रहा कि जब कॉप महत्वाकांक्षी कामों की रुपरेखा तैयार कर रहा है, तब वह चाहता है कि इन निर्णयों को जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के माध्यम से वास्तविकता का रूप दिया जाना चाहिए। भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा आगे का सफर तय करने से पहले यह स्वीकार किये जाने की जरूरत है कि जलवायु-न्याय के मामले में सबके साथ समानतापूर्ण व्यवहार किया जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है कि जीवाश्म ईंधन पर ज़रूरी सवाल - मसलन ऋण संकट और जलवायु से जुडी महत्वाकांक्षाओं के लिए वित्तीय मदद को कार्बन अवशोषण और भंडारण के अतिरिक्त ग्रीन वाश जैसे मसलों से भी टकराना होगा। प्राकृतिक गैस, स्वेच्छा कार्बन बाजार जैसे संक्रामक ईंधन और निजी क्षेत्र वित्त की मिथकीय भूमिका की समस्या से प्रबलता से निपटना होगा। और चूंकि जीवाश्म ईंधन की समाप्ति की सुस्पष्ट चरणबद्धता और समयसीमा के अभाव में जीएसटी परिणाम अत्यधिक त्रुटिपूर्ण हैं, ऐसे में आईईए के पास पहले से यह कार्यक्रम है कि इस दशक में जीवाश्म ईंधन की मांग अपने शीर्षतम बिंदु पर होगी। जीवाश्म ईंधन उद्योग इस सत्य से बखूबी परिचित हैं कि हरित तकनीक कीमतों को कम करने और विस्तृत अनुकूलन के सन्दर्भ में इस दौड़ में आगे है। यह बात महत्वपूर्ण है कि जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाने की आवश्यकता और स्वीकार्यता द्वारा निर्मित इस गतिशीलता का पूरा उपयोग नहीं होने की स्थिति में इस प्रक्रिया में और विलंब हुआ है। कॉप 29 की अध्यक्षता अजरबैजान के जिम्मे है, जो कि खुद एक गैस और तेल उत्पादक देश है। ऐसे में आशा है कि वह अपने उत्तरदायित्वों का भलीभांति निर्वहन करने से ही पूरी तरह सफल होगा। जलवायु-न्याय की दृष्टि से हमें अच्छी तरह यह पता है कि क्या कुछ करने की आवश्यकता है। अमीर और प्रदूषण फैलाने वाले देशों को वरीयता के क्रम पर अपनी अर्थव्यवस्था को कार्बन-मुक्त करना होगा। साथ ही यह प्राथमिकता में रखना होगा कि वह जीवाश्म ईंधनों पर अपनी निर्भरता को धीरे धीरे घटाएं। विकसित देशों को विकासशील देशों को वही साधन उपलब्ध कराने होंगे ताकि अपने विकास के लक्ष्यों की बलि चढ़ाए बगैर वे भी यह काम अधिक क्रमबद्धता के साथ कर सकें। विकासशील देशों को शमन और अनुकूलन के घरेलू उपायों को खोजने के लिए अधिक तत्पर होना होगा, और अगले कॉप सम्मेलन से पहले अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की रूपरेखा बनानी होगी। विकसित देशों को अगले कॉप को फाइनेंस कॉप का नाम देना होगा, जहां जलवायु वित्त पर सामूहिक और मात्रा-निर्धारित लक्ष्य निश्चित किया जाएगा। 2024 का वर्ष सिद्धांत को व्यावहारिकता का रूप देने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण वर्ष होगा।

जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए एशियाई वन विविधता बेहद जरूरी- अध्ययन

नई दिल्ली। एक अध्ययन में कहा गया है कि जंगल जलवायु परिवर्तन को रोकने में अहम भूमिका निभाते हैं, जबकि पेड़ों में विविधता जंगल के महत्व को और भी बढ़ा देती है। सिडनी विश्वविद्यालय की डॉ. रेबेका हैमिल्टन के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने पाया है कि 19,000 साल के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में शुष्क सवाना की अधिकता के बजाय, अलग-अलग तरह के ढके और खुले जंगल थे।

अध्ययन के निष्कर्षों से पता चलता है कि एशिया के उष्णकटिबंधीय वन पहले की तुलना में जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीले हो सकते हैं, बशर्ते कि उनकी विविधता बरकरार रखी जाए। वे आगे बताते हैं कि पूरे क्षेत्र में रहने वाले लोगों और जानवरों के पास पहले की तुलना में अधिक विविध प्राकृतिक संसाधन रहे होंगे। यह अध्ययन प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित हुआ है। सिडनी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ जियोसाइंसेज के डॉ. हैमिल्टन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन में तेजी आने के साथ, वैज्ञानिक और पारिस्थितिकी विज्ञानी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इसका दक्षिण पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि लचीलेपन की सुविधा प्रदान करने वाले वनों को बनाए रखना क्षेत्र के लिए एक अहम संरक्षण उद्देश्य होना चाहिए। अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि मौसम के अनुसार शुष्क वनों के प्रकारों के साथ-साथ 1000 मीटर से ऊपर के जंगलों, जिन्हें %पर्वतीय वन% भी कहा जाता है, इनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देना एशिया के वर्षावनों के भविष्य के %सवनीकरण% को रोकने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। सावनीकरण से तात्पर्य एक ऐसे परिदृश्य से है जो आमतौर पर एक वन क्षेत्र, के सवाना पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव से है, जिसमें आम तौर पर खुले जंगली मैदान शामिल होते हैं। यह परिवर्तन आम तौर पर जलवायु परिवर्तन, मानवीय हस्तक्षेप या प्राकृतिक पारिस्थितिक बदलाव के कारण होता है। शोधकर्ताओं ने सवाना मॉडल का परीक्षण करने के लिए उष्णकटिबंधीय दक्षिण पूर्व एशिया में 59 पुरापर्यावरण स्थलों के रिकॉर्ड का विश्लेषण किया, जिसमें लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम या अंतिम ग्लैशियल के दौरान पूरे क्षेत्र में एक बड़े, समान घास के मैदान का विस्तार माना गया था। उन्होंने पाया कि झीलों में संरक्षित पराग कणों के रिकॉर्ड से पता चलता है कि इस अवधि के दौरान घास के मैदानों के विस्तार के साथ-साथ जंगल भी मौजूद थे, जिनका पता अन्य जैव रासायनिक संकेतों से चलता है। डॉ. हैमिल्टन ने कहा, हमने इस विचार को सामने रखा कि इन विसंगतियों को सुलझाया जा सकता है, यदि लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम की ठंडी जलवायु के दौरान, पर्वतीय वन, जो 1000 मीटर से ऊपर उगते हैं, और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विस्तारित हुए, जबकि तराई क्षेत्रों में मौसमी शुष्क वनों की ओर स्थानांतरण हुआ, जिनमें प्राकृतिक रूप से घास के मैदान हैं। शोधकर्ताओं ने कहा उन्हें उम्मीद है कि कई पुरापारिस्थितिकी रिकॉर्डों की तुलना करने के लिए विकसित सांख्यिकीय तरीके अन्य पिछले पारिस्थितिक परिवर्तनों के क्षेत्रीय परीक्षण के लिए उपयोगी होंगे।

पर्यावरण की स्थिति हो रही दिन प्रतिदिन खराब -डॉ. एचडी

कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय एवं पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के सहयोग से राष्ट्रीय पर्यावरण यूथ संसद 2024 कम्यूनिटी बेस्ड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर विषय पर ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई।

इस प्रतियोगिता में बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. एचडी चरण मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। मानव ही समस्या का कारण है। मानव को अपनी आदतों में सुधार करना होगा और जरूरतों को कम करना होगा। जीडीपी बेस्ड अवधारणा ही विनाश का कारण है। पड़ोसी देश भूटान जीडीपी को अपना विकास नहीं मानता। वह व्यक्ति की खुशी को विकास मानता है। वसुधैव कुटुंबकम के भाव से जीवन जीना चाहिए। डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रो. अनिल वशिष्ठ ने कहा कि ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से युवाओं में पर्यावरण के प्रति संवेदना व चेतना हमारे व्यवहार में आना शुरू होती है। हमेशा कुछ नया सृजित करते रहने का प्रयास करना चाहिए। छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. एआर चौधरी ने कहा कि पर्यावरणीय समस्याओं के निवारण के लिए आज हमारा समाज एकजुट व जागरूक हो रहा है। यह कार्यक्रम युवाओं के लिए एक बेहतर अवसर प्रदान करेगा। प्रतिनिधि श्रीभगवान ने कहा कि प्रत्येक देश बेरोजगारी, आतंकवाद जनसंख्या व अन्य किसी न किसी समस्या से ग्रस्त है, लेकिन पूरा विश्व पर्यावरण की समस्या से जूझ रहा है। मानव को अपना व्यवहार बदलना होगा तभी पर्यावरण संरक्षण हो पाएगा और सुंदर वातावरण स्थापित हो पाएगा। इस मौके पर डॉ. मीनाक्षी सुहाग, उपासना, प्रो. विक्रम कौशिक, डॉ. आर भास्कर, डॉ. दीपक राय बब्बर, डॉ. वीर विकास, डॉ. रमेश कुमार, डॉ. लता खेड़ा, डॉ. विशाल अहलावत, डॉ. सुमन बाला सहित विद्यार्थी व शोधार्थी मौजूद रहे।

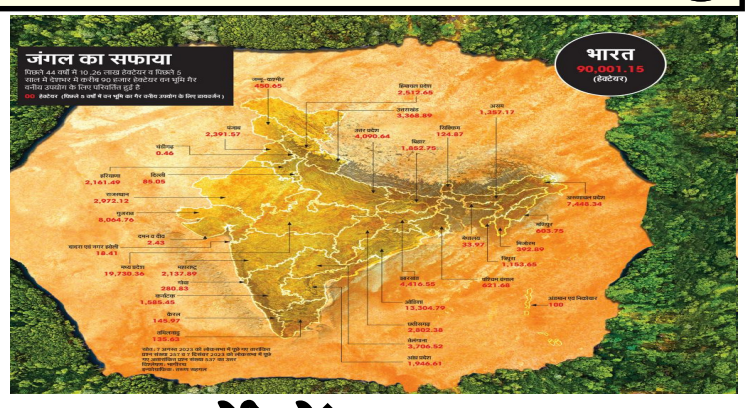

44 वर्षों में 10.26 लाख हेक्टेयर जंगल साफ

नई दिल्ली साल 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बनने के बाद से अब तक देशभर में लगभग 10 लाख 26 हजार हेक्टेयर वन भूमि का गैर वनीय उपयोग के लिए डायवर्जन हुआ है। यह भूमि दिल्ली के भौगोलिक क्षेत्रफल से लगभग 7 गुना अधिक है। उदारीकरण से ठीक पहले साल 1990 में सर्वाधिक 1 लाख 27 हजार से अधिक वन भूमि का डायवर्जन हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा डायवर्जन साल 2000 में हुआ। इस साल 1 लाख 16 हजार से अधिक वन भूमि गैर वनीय उपयोग के लिए डायवर्ट की गई। 7 अगस्त 2023 को लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने बताया कि पिछले 15 वर्षों (2008-09 से 2022-23) में 3,05,756 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्जन हुआ है। वहीं अगर पिछले 5 वर्षों के आंकड़ों को देखें तो करीब 90 हजार हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्जन हुआ है। अप्रैल 2018 से मार्च 2023 के बीच देशभर के 33 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की सबसे अधिक वन भूमि सड़क और खनन के लिए ली गई है। पिछले पांच सालों में कुल 90 हजार हेक्टेयर में से सड़क (19,497 हेक्टेयर) और खनन (18,790 हेक्टेयर) के लिए 38,767 हेक्टेयर (43 प्रतिशत) भूमि का डायवर्जन हुआ है। ट्रांसमिशन लाइन व सिंचाई के लिए 10 हजार हेक्टेयर से अधिक वन भूमि का उपयोग किया गया है। रक्षा से जुड़ी परियोजनों के लिए 7,631 हेक्टेयर, हाइड्रो परियोजनों के लिए 6,218 हेक्टेयर और रेलवे के लिए 4,770 हेक्टेयर भूमि का डायवर्जन किया गया है। इनके अतिरिक्त नहरों, अस्पताल/डिस्पेंसरी, पेयजल, वनग्रामों के कन्वर्जन, उद्योग, ऑप्टिकल फाइबर केबल, पाइपलाइन, पुनर्वास, स्कूल, सौर ऊर्जा, ताप ऊर्जा, पवन ऊर्जा, गांवों में विद्युतीकरण की परियोजनाओं के लिए भी वन भूमि का बड़े पैमाने पर डायवर्जन हुआ है।

नवागत कलेक्टर को पौधा भेंट कर किया सम्मान, पर्यावरण संरक्षण की मुहिम 25 वर्षों से जारी है

बैतूल। पर्यावरण बचाना हमारा सबका कर्तव्य है। हम सबको आगे आकर इस मुहिम में सहभागी होना होगा। इसी उद्देश्य को लेकर मंगलवार को नवागत कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी के आगमन पर अनोखे तरीके से उनका स्वागत किया गया। जिसमें फूलमाला से नहीं बल्कि पर्यावरण बचाओ-जनजाग्रति लाओ अभियान के तहत पर्यावरणविद किराड समाज के युवा मदनलाल डढोरे ने पौधा भेंट कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ सहित उपस्थितजनो ने कहा कि ऐसे कार्यो से समाज में पर्यावरण बचाने के प्रति जागरूकता आएगी। इस अवसर पर अनेक अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। पर्यावरण बचाने व अधिक से अधिक बचाने की जनमानस में जनजाग्रति लाने के उद्देश्य को लेकर श्री डढोरे द्वारा विगत वर्षो से आतिथ्य सत्कार, जन्मदिन, श्रद्धांजली, विवाह वर्षगांठ, धार्मिक कार्यक्रम सहित अनेक समाजिक कार्यक्रमों में स्वयं के व्यय पर लोगों को पौधे लगाने के लिए प्रेरित करते हैं और भेंट भी करते हैं। पर्यावरण बचाने का श्री डढोरे का जुनुन ऐसा है कि विगत वर्षो से निरंतर एक या दो दिन में पर्यावरण के लिए कार्य किया जा रहा है। उनका कहना है कि जीवन की अंतिम सांस तक यह मूहिम जारी रहेगी। सभी समाजसेवियों, सामाजिक संगठनों और युवाओं से श्री डढोरे ने आव्हान किया है कि सभी लोग अपने व आने वाली पीढी को बचाने के लिए जन्मदिन व वर्षगांठ पर अवश्य पौधारोपण करें जिसमें हम सबका हित है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008